

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २। दिसम्बर, 2011

विषय:- पिथौरागढ़ में तकनीकी विश्वविद्यालय के संगठक के रूप में सीमान्त इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना हेतु 4.2 है० भूमि, तकनीकी शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-ज्ञाप/भूमि चयन/2011 दिनांक-16.7.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, पिथौरागढ़ में तकनीकी विश्वविद्यालय के संगठक के रूप में सीमान्त इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना हेतु वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक-15.02.02 में निहित प्राविधानों एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत, आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित ग्राम मण (मणधूरा) पट्टी जीवी, पिथौरागढ़ में खाता संख्या-100 श्रेणी 9 (3) ड अन्य कृषि योग्य बंजर मध्ये कुल 4.2 है० भूमि, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार, तकनीकी शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या ३ वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ० ०० संख्या—३१२। / समिति कित / 2011

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 5— प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।